नईदुनिया

संपादकीय

नई प्रतिभाओं को मौका देता आईपीएल

चेन्नै *सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शुक्रवार को हुए मुकाबले के साथ ही आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत हो गई। दो महीने चलने वाला यह इवेंट देश में एक ऐसे मौसम का रूप लेता जा रहा है, जो घर-घर में रुटीन बदल देता है। लोग देर रात मैच खत्म होने के बाद सोते हैं और फिर अगली सुबह समय पर दफ्तर पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे दिखते हैं। बहरहाल, इस बार कुछ ऐसी बातें हैं, जो आईपीएल के इस सीजन को खास बनाती हैं। आईपीएल के इस सीजन में पहली बार 'स्मार्ट रीप्ले सिस्टम' दिखने वाला है। इसमें टीवी अंपायर के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा फोटो विश्लेषण का मौका होगा। जाहिर है, इससे अंपायर कैच, स्टंपिंग और एलबीडब्ल्यू आदि पर ज्यादा सटीक फैसला देंगे और दर्शक भी फैसले के पीछे की प्रक्रिया बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मुंबई इंडियंस ने तो आईपीएल सीजन शुरू होने से काफी पहले रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पंड्या को नया कप्तान घोषित कर दिया था। सीजन शुरू होने के ऐन पहले एम एस धोनी ने भी चेन्नै सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया। वह जिम्मेदारी रितुराज गायकवाड़ के कंधों पर आई है। गुजरात टाइटंस (शुभमान गिल) और हैदराबाद (पैट कमिंस) की टीमें भी इस बार नए कप्तान की अगुआई में मुकाबले में उतर रही हैं। आईपीएल के इस 17वें सीजन को इस लिहाज से भी खास माना जा रहा है कि यह पूरा मुकाबला लोकसभा चुनावों के साये में संपन्न होगा। 22 मार्च से 26 मई तक चलने वाला 66 दिनों का कार्यक्रम इसे आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा सीजन बना देता है। लेकिन चुनाव उससे भी आगे खिंचने वाले हैं। सातवें और आखिरी दौर का मतदान 1 जून को होगा और रिजल्ट 4 जून को आएगा।*

हालांकि इससे पहले 2019 में भी लोकसभा चुनावों के दौरान पूरा आईपीएल देश में खेला जा चुका है, लेकिन इस बार इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया का ब्रैंड आईपीएल पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे अब तक का अनुभव देखा जाए तो ब्रैंड आईपीएल तमाम बाधाओं के बावजूद मजबूत ही होता रहा है। 2020 में महामारी के दौरान भी कैलेंडर और वेन्यू बदलने के बावजूद बीसीसीआई ने आईपीएल से कमाई की। फिर भी मीडिया और दर्शकों की दोहरी प्राथमिकता के बीच अगर आईपीएल अपना आकर्षण बनाए रखता है तो यह निश्चित रूप से स्पोर्ट्स की दुनिया में उसका कद बढ़ाएगा।

लेफ्ट जेएनयू से जेएनयू तक

दृष्टिकोण

-आर.के. सिन्हा

हैरानी तो इस बात की है कि जेएनयू के नतीजों पर अपनी राय रखने वाले कुछ माह पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजों की पूरी तरह अनदेखी कर गए। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर कब्जा जमाया था। एक पद पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को भी जीत मिल थी। जहां सारे जेएनयू में करीब पांच हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के अकेले दयाल सिंह कॉलेज में 8 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि छात्रों की संख्या के स्तर पर जेएनयू कितना छोटा सा शिक्षण संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) छात्रसंघ चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों को सफलता मिलने के बाद जिस तरह से कुछ कथित बुद्धिजीवी कहे जाने वाले विद्वानों ने सोशल मीडिया में टिप्पणियां की हैं, उन्हें हास्यास्पद ही माना जाएगा। इन विद्वानों ने लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों की कामयाबी को आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी जोड़ा। यहां तक कह दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं। जेएनयू में अध्यक्ष समेत सभी चारों सीटों पर वामपंथी दलों के छात्र संगठनों और उनके समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिली है। जिस जेएनयू में करीब 5 हजार विद्यार्थी पढ़ते हों उसके छात्रसंघ के नतीजों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना मूर्खता नहीं, तो क्या है।

हैरानी तो इस बात की है कि जेएनयू के नतीजों पर अपनी राय रखने वाले कुछ माह पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजों की पूरी तरह अनदेखी कर गए। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर कब्जा जमाया था। एक पद पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को भी जीत मिल थी। जहां सारे जेएनयू में करीब पांच हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के अकेले दयाल सिंह कॉलेज में 8 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि छात्रों की संख्या के स्तर पर जेएनयू कितना छोटा सा शिक्षण संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में।

दरअसल वामपंथी विचारधारा और लेफ्ट दल पूरी तरह से भारतवर्ष में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सब दल तैयारी कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, वहां लेफ्ट दलों की तरफ से कोई हलचल तक नजर नहीं आ रही है।

2014 के लोकसभा चुनाव में उसे मात्र 11 सीटें ही मिलीं। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में माकपा या भाकपा को एक भी सीट नहीं मिली। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ संदेश दे दिया था कि देश के मतदाताओं ने लेफ्ट दलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन नतीजों के बाद लेफ्ट पार्टियों के सीताराम येचुरी, डी.राजा और वृंदा करात जैसे नेता सिर्फ संवाददाता सम्मेलनों और सेमिनारों में ही नजर आते हैं। अपनी पहचान बचाने के लिये पूरी तरह से संघर्षरत नजर आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों शराब घोटाले में हिरासत में लिया गया तो डी.राजा और उनकी पार्टी भाकपा के कुछ नेता तुरंत केजरीवाल के सरकारी घर में उनकी पत्नी से मिलने पहुंच गए। वहां उन्होंने खबरिया चैनलों को बाइट दी और बस हो गई उनकी क्रांति।

लेफ्ट दलों के मौजूदा नेता कभी किसी जन आंदोलन का हिस्सा तक नहीं होते। हां, वे किसी आंदोलन से अपने को मौके के अनुसार जोड़ लेते हैं। जब कुछ किसान एमएसपी को लेकर आंदोलनरत थे, तब लेफ्ट दलों के नेता उनके पास मंच में जाकर बैठने लगे थे। इन नेताओं के विपरीत गुजरे दौर के लेफ्ट दलों के नेता जैसे हरिकिशन सिंह सुरजीत, नम्बुदिरीपाद, इंद्रजीत गुप्त, ज्योति बसु, चतुरानन मिश्र, रामावतार शास्त्री, भोगेन्द्र झा वगैरह काफी जुझारू हुआ करते थे। उन्हें जमीनी हकीकत की बेहतर जानकारी थी।

वैचारिक मतभेदों के बावजूद ईएमएस नम्बुदिरीपाद की सादगी और विद्वता का सब सम्मान करते थे। वह 1978 में माकपा के महासचिव बने तो उन्हें पार्टी ने राजधानी के 20 जनपथ की कोठी दी रहने और काम करने के लिए। वह 20 जनपथ में तब तक रहे जब तक वह माकपा के महासचिव के तौर पर दिल्ली में रहे। जब हरकिशन सिंह सुरजीत महासचिव बने तब ईएमएस त्रिवेंद्रम चले गए। बिहार माकपा के नेता और ईएमएस के सहयोगी रहे श्री भगवान प्रसाद सिन्हा बताते हैं कि ईएमएस सुबह पांच बजे उठ जाते थे। प्रात:काल की सैर के साथ वह साइकिल से व्यायाम करनेवालों में से भी थे। उसके बाद वे अखबार पढ़ते, नाश्ता लेते और ठीक आठ बजे पार्टी दफ्तर जो पटेल चौक के समीप 14, अशोक रोड पर था जाने के लिए तैयार हो जाते। ईएमएस को चलने में कठिनाई थी। लेकिन, चाहे घर 20 जनपथ में या चाहे दफ्तर 14, अशोक रोड में वे चाय पीने के बाद कप धोने के लिए दो कमरे को पारकर किचेन रूम तक पहुंच जाते। वे कम्युनिस्ट होते हुए भी राजनीति में गांधी जी की तरह एक सादा जीवन जिए, सारी जमीन जायदाद पार्टी को दान कर दी। भारत की राजनीति में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है।

पर अब ईएमएस जैसे नेता लेफ्ट दलों के पास रहे कहां सच्चाई तो यह है कि अब लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा से निकलकर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक सिमट गई हैं। वहां के छात्रसंघ के चुनाव जीतकर इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने सर्वहारा की देश में क्रांति कर दी या करने ही वाले हैं। देश ने इनका पहली बार वीभत्स चेहरा देखा 1962 में चीन से जंग के वक्त। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(भाकपा) ने राजधानी के बारा टूटी चौक में चीन के समर्थन में एक सभा तक आयोजित करने की कोशिश की थी। यह अलग बात है कि स्थानीय जनता के भारी विरोध के कारण भाकपा की सभा नहीं हो सकी थी। कुछ वर्ष पूर्व इन्हीं लेफ्ट दलों का पोस्टर ब्वाय कन्हैया कुमार ने जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव जीता था। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने अपना उम्मीदवार भी बनाया था। वह चुनाव में बुरी तरह से हार गया था। उसके बाद उसने कांग्रेस का रुख कर लिया। यह वही कन्हैया कुमार है, जिसने भाकपा में रहते हुए भारतीय सेना पर कश्मीर में रेप तक करने के आरोप लगाए थे।

कन्हैया कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए टुकड़े-टुकड़े गैंग ने बेगूसराय में डेरा डाला हुआ था। यह सब सोशल मीडिया पर इस तरह का माहौल बना रहे थे कि मानो भारतीय सेना को बलात्कारी कहने वाला कन्हैया कुमार भाजपा के गिरिराज सिंह को हरा ही देगा। कन्हैया कुमार 2024 के चुनाव कांग्रेस की टिकट पर फिर चुनाव लड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह कि लेफ्ट दलों के लिए भारतीय राजनीति में स्पेस तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। उनके लिए अपनी पुरानी जमीन को हासिल करना कतई आसान नहीं है। फिर लेफ्ट दल और उनके नेता और समर्थक भी जेएनयू तक ही रहने में बहुत बड़ी कामयाबी मानने लगे हैं।

मोदी की रैली में जयंत के साथ रहेंगे राम

नजरिया

डॉ. प्रभात ओझा

प्रधानमंत्री की रैली में स्वाभाविक है कि मेरठ के अतिरिक्त जयंत चौधरी के प्रभाव वाले क्षेत्रों के बड़ी संख्या में समर्थक शामिल होंगे। इनमें बिजनौर और बागपत से, जहां से आरएलडी प्रत्याशी हैं, उनके अतिरिक्त मुजफ्फरनर से लेकर कैराना और खतौली से सहारनपुर तक जाट प्रभावित इलाके इस बार क्या फैसला करते हैं, यह देखना होगा। पिछली बार तो उन्होंने जाटों के प्रतीक पिता-पुत्र के हिस्से पराजय ही दी थी। अब सवाल है कि कम होते असर के बावजूद भाजपा जयंत के दल को महत्व क्यों दे रही है। इसे समझने के लिए देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के साथ मेरठ, अलीगढ़ और आगरा के उन 18 जाटबहुल क्षेत्रों पर भी पार्टी की नजर है, जहां वह बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मेरठ से करने जा रहे हैं। पहले ही ध्यान रखना होगा कि मोदी ने 2019 में और उसके पहले 2014 में भी इसी धरती पर पहली चुनावी रैली को संबोधित किया था। पिछली बार यह रैली 28 मार्च को हुई थी, तो इस बार 30 को होने जा रही है। पिछले चुनाव के पहले चरण में इस जाटलैंड में जिन आठ सीटों पर मतदान हुआ था, उनमें से भाजपा को छह सीटें हासिल हुई थीं। बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर और सहारनपुर, दो लोकसभा क्षेत्र अपने नाम किया था। तब बसपा और सपा के बीच बुआ-भतीजे की जोड़ी कारगर हुई थी। इन दोनों दलों ने राष्ट्रीय लोकदल को भी समर्थन दिया था किंतु प्रमुख जाट नेता चौधरी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी हार गए थे। दोनों पिता-पुत्र मजफ्फरनगर और बागपत से उम्मीदवार थे। चौधरी अजीत सिंह अब नहीं हैं और जयंत चौधरी ने तब से कई राजनीतिक पैंतरे बदले। फिलहाल वे सपा का साथ छोड़कर भाजपा से हाथ मिला चुके हैं और निश्चित ही वे प्रधानमंत्री के मंच पर दिखाई देंगे। काफी कुछ सोच विचार कर उन्होंने सपा से मिल रही कुछ अधिक सीटों के मुकाबले भाजपा से सिर्फ दो पर समझौता किया है। वे स्वयं चुनाव मैदान में नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में बनाए रखने का फैसला किया है। चौधरी की पार्टी बिजनौर और बागपत से भाजपा के सहयोग के साथ मैदान में है।

प्रधानमंत्री की रैली में स्वाभाविक है कि मेरठ के अतिरिक्त जयंत चौधरी के प्रभाव वाले क्षेत्रों के बड़ी संख्या में समर्थक शामिल होंगे। इनमें बिजनौर और बागपत से, जहां से आरएलडी प्रत्याशी हैं, उनके अतिरिक्त मुजफ्फरनर से लेकर कैराना और खतौली से सहारनपुर तक जाट प्रभावित इलाके इस बार क्या फैसला करते हैं, यह देखना होगा। पिछली बार तो उन्होंने जाटों के प्रतीक पिता-पुत्र के हिस्से पराजय ही दी थी। अब सवाल है कि कम होते असर के बावजूद भाजपा जयंत के दल को महत्व क्यों दे रही है। इसे समझने के लिए देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के साथ मेरठ, अलीगढ़ और आगरा के उन 18 जाटबहुल क्षेत्रों पर भी पार्टी की नजर है, जहां वह बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी। इसीलिए मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान को मंत्री पद दिया गया, तो मुरादाबाद के भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद भी चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी का किसानों, खासकर जाट किसानों में असर बना हुआ है। जयंत के समाजवादी पार्टी के साथ जाने से मुस्लिम-जाट समीकरण को भी ताकत मिल रही थी। अब जबकि जयंत सपा का साथ छोड़ आए, भाजपा ने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है।

मुस्लिम-जाट एका टूटने के संकेत के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपनी मेरठ की रैली से एक और बड़ा संदेश दे सकते हैं। कम लोगों के ध्यान में है कि मेरठ की रैली में मंच पर पार्टी उम्मीदवार अरुण गोविल भी रहेंगे। गोविल ने अपने जमाने के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में राम का रोल निभाया था। देखा जाए तो इस धारावाहिक के अलावा अरुण गोविल को फिल्म अथवा छोटे परदे पर बहुत जगह नहीं मिली। इस तरह वह लोगों की नजर से अंतर्ध्यान ही रहे किंतु अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम का हर प्रतीक महत्वपूर्ण लगने लगा है। भाजपा और उसके नेता नरेन्द्र मोदी इस अवसर को इसकी चर्चा के बिना जाने देंगे, यह मुमकिन नहीं लगता। तो जाट-मुस्लिम गठजोड़ तोड़ने के साथ ही हिंदू मतों का ध्रुवीकरण मेरठ रैली का मूल मकसद होगा और पूरे उत्तर भारत में इस प्रयोग को अमल में लाने की तैयारी हो चुकी है।

आजकल

बढ़ती तपिश से खेती पर संकट

सच है कि ग्लोबल वॉर्मिंग ने हमारे खेत-खलिहानों में दस्तक दे दी है। जिस गति से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वह आम आदमी के लिये तो कष्टकारी है ही, किसान के लिये संकट ज्यादा बढ़ा है। इसका सीधा असर खेतों की उत्पादकता पर पड़ रहा है। जिसके मुकाबले के लिये सुनियोजित तैयारी की जरूरत है। किसानों को उन वैकल्पिक फसलों के बारे में सोचना होगा, जो कम पानी व अधिक ताप के बावजूद बेहतर उत्पादन दे सकें। अन्न उत्पादकों को धरती के तापमान से उत्पन्न खतरों के प्रति सचेत करने की जरूरत है, यदि समय रहते ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए कि हम आसन्न संकट की अनदेखी कर रहे हैं। यह मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुद्दा दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की खाद्य शृंखला से भी जुड़ा है। यानी गाहे-बगाहे इस संकट की जद में देश का हर नागरिक आएगा। दरअसल, दुनिया के तापमान पर निगाह रखने वाली वैश्विक संस्था डब्ल्यू.एम.ओ.की वह रिपोर्ट चिंता बढ़ा रही है जिसमें कहा गया है कि पिछले एक दशक में पृथ्वी का तापमान कमोबेश औसत तापमान से अधिक ही रहा है। फिक्र की बात यह है कि इसके मौजूदा साल में और अधिक रहने की आशंका जतायी जा रही है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से पूरी दुनिया का मौसम चक्र गहरे तक प्रभावित होता है। देर-सबेर इससे मनुष्य जीवन का हर पहलू प्रभावित होगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल वॉर्मिंग संकट के चलते पूरी दुनिया में यह कह पाना कठिन है कि कहां अप्रत्याशित बारिश होगी और कहां कष्टकारी तापमान बढ़ेगा। लेकिन इसके बावजूद विकसित देशों की सरकारें इस गंभीर संकट के प्रति सचेत नजर नहीं आती। ऐसे में आशंका जतायी जा रही है कि इस सदी के मध्य तक दुनिया का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। जो मानव जीवन चक्र व फसलों के लिये घातक साबित हो सकता है।

यह सर्वविदित है कि दुनिया के बड़े राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाने के लिये प्रतिबद्ध नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया में बड़े राष्ट्र विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन करने में लगे हैं। वे इस बात को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं कि आज दुनिया में औद्योगिकीकरण से पहले के समय के मुकाबले विश्व का तापमान निर्धारित सीमा को पार कर चुका है।

भारत सतर्क रहे मास्को में हुए आतंकवादी हमले से

पुष्परंजन

मास्को के क्रॉकस सिटी हाल पर 22 मार्च को भयावह आतंकी हमले के सिलसिले में जिन चार ताजिकों पर कोर्ट ट्रायल चल रहा है, उनकी नागरिकता की ज़िम्मेदारी लेने से ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने पल्ला झाड़ लिया है। ताजिक राष्ट्रपति ने पुतिन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। करीब 137 लोगों की हत्या करने वालों के साथ आपको जैसा सुलूक करना हो, करें। जिन चार ताजिकों की तुड़ाई रशियन जांच एजेंसियों ने की है, उन लोगों की पहचान सैदाक्रम राजाबलीजोडा, दलेरजोन मिर्जोव, मुहम्मद सोबिर फैजोव और फरीदुन शम्सिद्दीन के रूप में की गई है।

अदालत ने कहा कि बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान चार में से तीन लोगों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। रूसी मीडिया रिपोर्टों में 11 गिरफ्तारियां बताई गई थीं। मगर, चार के बाद वो बाकी लोग कौन हैं? यह सवाल अनुत्तरित है। यूक्रेन बार-बार पल्ला झाड़ रहा है कि इस हमले से हमारा कोई लेना-देना नहीं। पुतिन ने इस कांड का पूर्वाभास देने वाले अमेरिका के विरुद्ध अलग से मोर्चा खोल रखा है। ख़बर यह बन रही है कि यह सब सीआईए का किया-कराया है, जिसके तार यूक्रेन से जुड़े हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, रूसी इंटेलीजेंस की विफलता। पुतिन इस चूक को मानने से इनकार कर रहे हैं। मगर, पुतिन के विरोधी बोल रहे हैं कि रूसी इंटेलीजेंस के लोगों को केवल सिस्टम की आलोचना करने वालों के पीछे लगा रखा है, इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं।

दूसरी ओर ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के बयान के बाद उनके देश में ही राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी इस्लामिक रेनेसां पार्टी ऑफ ताजिकिस्तान (आईआरपीटी) के नेता मुहिद्दीन कबीरी ने अपने कुछ नागरिकों को कट्टरपंथी बनाने के लिए इमोमाली रहमान की तानाशाह नीतियों और इस्लाम के विरुद्ध कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया है। 'आईआरपीटी' जो कभी सरकार में सहयोगी थी, अब ताजिकिस्तान में प्रतिबंधित है। रूसी सांसद अलेक्जेंडर खिनशेटिन ने टेलीग्राम पर लिखा कि कार के अंदर ताजिक पासपोर्ट पाए गए थे, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर संदिग्धों ने मॉस्को से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में ब्रांस्क क्षेत्र में रूसी पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले किया था।

राजाबलीजोडा, वह शख्स है, जिसका कोर्ट ट्रायल हो रहा है। एक वीडियो क्लिप में उसे मॉस्को हमले में भाग लेने की बात कबूल करते हुए दिखाया गया है। वीडियो फुटेज में रूसी सुरक्षा अधिकारियों को उस शख्स का कान काटते हुए दिखाया गया है। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई और चेहरा और टी-शर्ट खून से लथपथ भी दिखाया गया है। उस व्यक्ति का कहना है कि हमले के स्थान से भागते समय उसने और उसके अन्य साथियों ने अपने हथियार सड़क पर कहीं छोड़ दिए थे। ताजिक लहजे में रूसी बोलते हुए, एक और शख्स फरीदुन शम्सिद्दीन वीडियो फुटेज में कह रहा है कि अंधाधुंध गोलियां बरसाने के लिए उसे एक मिलियन रूबेल देने की पेशकश की गई थी। ऐसे वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि भी एक अलग चुनौती है। संदिग्धों में 19 वर्षीय मुहम्मद सोबिर फैजोव भी शामिल है, जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे का रहने वाला है। फैजोव कथित तौर पर गिरफ्तारी से पहले घायल हो गया था, जिसका ब्रांस्क अस्पताल में इलाज किया गया है। रूसी मीडिया की रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप्स ने प्रवासी ताजिक नागरिकों पर शामत ला दी है। रूस, सेंट्रल एशियाई देशों के लाखों श्रमिकों के लिए घर जैसा है। रूस में 18 से 20 लाख के लगभग ताजिक मूल के लोग हैं। वहां क्रॉकस सिटी हाल हत्याकांड से लोग इतने आहत और गुस्से में हैं कि ताजिक विरोधी दंगे भी कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। सुदूर पूर्वी शहर ब्लागोवेशचेंस्क में ताजिक प्रवासियों द्वारा चलाए जा रहे एक कैफेटेरिया में आग लगा दी गई, जबकि पश्चिमी रूसी शहर कलुगा में कथित तौर पर तीन ताजिकों को पीटा गया। कई रूसी शहरों में ड्राइवर ताजिक होने का पता लगते ही टैक्सी सेवा के ग्राहक कथित तौर पर अपना ऑर्डर रद्द करने लगे। ताजिक के शक में सेंट्रल एशियाइयों के विरुद्ध भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगी हैं। गत 23 मार्च को मॉस्को के शेरेमेतयेवो हवाई अड्डे पर दर्जनों किर्गिज पुरुषों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग 24 घंटों तक कोई भोजन या पानी नहीं मिला है, और महिलाओं और बच्चों को किर्गिस्तान की उड़ानों में वापस भेज दिया गया है।

सेंट्रल एशिया में अवस्थित ताजिकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था जिसके विघटन के बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश बना। 1992 से 1997 के कालखंड में गृहयुद्धों की मार झेल चुके इस देश की कूटनीतिक-भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यह उजबेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिजस्तान तथा चीन के मध्य स्थित है। उत्तरी पाकिस्तान का पतला-सा वाखान गलियारा भी इसे जोड़ता है। ताजिकिस्तान की भाषा ताजिक फारसी का ही एक रूप है।